**मलिक राम**
**बनाम**
**राजस्थान राज्य**
**(पी.बी. गजेन्द्रगाडकर, ए. के. सरकार,**
**के. एन.वांचू, के. सी दास गुप्ता और**
**एन. राजगोपाला अय्यंगर,जे.जे )**

मोटर वाहन– योजना पर आपत्ति– ऐसी आपत्ति को सुनने के लिए नियुक्त अधिकारी की की शाक्ति– रिकॉर्डिग साक्ष्य—योजना को रद्द करना– मोटर वाहन अधिनियम, 1993(1939 का 4),धारा 68– डी(2) – राजस्थान राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियम, 1960 आर. 7(6).

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68– डी (2) के द्वारा ," राज्य सरकार आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात और आपत्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों को एक अवसर देने और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधि को मामले में सुनवाई, यदि वे ऐसा चाहते हैं,तो अनुमोदन करते हैं या योजना को संशोधित करें"। मसौदे पर अपीलकर्ता की आपत्तियां विचाराधीन योजना को कानूनी स्मरण द्वारा सुना गया, ऐसी आपत्तियों को सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्ती, अन्तर्गत नियम 7 (6) राजस्थान राज्य परिवहन सेवा (विकास) नियम, 1960,की धारा 68–।,अधिनियम के तहत बनाये गये। अपीलकर्ता ने अनुमति के लिए उक्त अधिकारी को सबूत देने के लिए आवेदन दिया ताकि वह उसे पूरा दिखा सके कि पूरी योजना को खारिज कर देना चाहिए। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। आधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है साक्ष्यों की रिकॉर्डिग और राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 9 नबम्बर 1960,के निर्णय के अनुसार,अधिनियम की धारा 68– डी (2), उन्हे मसौदा योजना को पूर्णतः रद्द करने का अधिकार नहीं देती है। उन्होंने इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से संबोधित दलीलें सुनीं और योजना को मंजूरी दी। पश्चात् असफल रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय का रूख किया अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील की।

यह अभिनिर्धारित, अधिकारी दोनों बिंदुओं पर गलत था। अधिनियम की धारा 68–डी (2) का स्पष्ट अर्थ है कि जिस प्राधिकरण को योजना को अनुमोदित या संशोधित करना है, उसके पास शाक्ति भी है, यदि वह उचित समझे, योजना को पूर्णतः अस्वीकार कर सकेगी। अनुभाग में "अनुमोदन हो सकता है" शब्दों का, उचित अर्थ लगाया गया है, जिसमें "अनुमोदन नहीं हो सकता है" भी शामिल होना चाहिए।

नियमों के नियम 7(6)में "करेगा" शब्द का उपयोग के बजाय शब्द " हो सकता है" का, जो अन्यथा अपने शब्दों में समान है,से अधिनियम की धारा 68–डी (2) ,पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है।

अधिनियम के धारा 68– डी (2) के तहत आपत्तियों की सुनवाई में, राज्य सरकार या उसके अधिकारी अर्थ– न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और आपत्तियों की प्रकृति और इसके तहत सुनवाई का उद्देश्य,को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य का उत्पादन, पर अनुभाग द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किया गया।

*गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट रोड परिवहन निगम, [1959]* सप्लिमेंट। 1 एस. सी. आर 319, संदर्भित को।

लेकिन का मतलब यह नहीं है कि पार्टियाँ केवल कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए कोई भी साक्ष्य की मात्रा का उत्पादन कर सकती हैं। यह राज्य सरकार या अधिकारी को यह तय करना है कि क्या प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य आवश्यक और प्रासंगिक है जांच के लिए और यिद हां, तो उनके पास सभी शाक्तियां होंगी कि एक अदालत को ऐसे साक्ष्य देने और रिकार्ड को नियंत्रित करने की है। जहां एक मसौदा योजना को धारा 68–डी (2) के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है और इस प्रकार, खारिज कर दिया जाता है, किसी भी नई योजना जिसे तैयार करना पड़ सकता है, उसे अध्याय IV–A द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

**सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 1961 की सिविल अपील संख्या 135.**

**1961 की सिविल रिट याचिका संख्या 1 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के 3 जनवरी, 1961 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।**

**अपीलकर्ता याचिकाकर्ता की ओर से** *एम.के. नांबियार, आरके गर्ग, डीपी सिंह, एमके रामामूर्ति और एस. सी अग्रवाल।*

**प्रतिवादियों की ओर से** *एचएन सान्याल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर–जनरल, जी. सी कासलीवाल, राजस्थान के महाधिवक्ता, खान सिंह और डी. गुप्ता।*

1961 की 14 अप्रेल। न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

वांचू, जे– ये दो जुड़े हुए मामले मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय IV–A, 1939 के क्रमांक IV(इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत बनाई गई एक योजना को मंजूरी देने वाले आदेश से उत्पन्न हुए हैं और एक साथ निपटाया जाएगा। वर्तमान प्रयोजनों के लिए आवश्य संक्षिप्त तथ्य ये हैं। अपलीकर्ता क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 16/17 दिसंबर, 1958 के संकल्प द्वारा तीन साल के लिए दिए गए परमिट पर जयपुर और अजमेर के बीच बस चला रहा था। अगस्त, 1960 में, राज्य सरकार ने अधिनियम के धारा 68–1, जिसे राजस्थान राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियम 1960 कहा जाता है (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) के तहत नियम प्रख्यापित किए। अध्याय IV–A के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाए गए थे और *अन्य बातों के साथ–साथ* योजनाओं को तैयार करने, आपत्तियों की सुनवाई, मुआवजे का निर्धारण और भुगतान और अन्य आनुषांगिक मामलों के लिए प्रावधान किया गया। जयपुर–अजमेर मार्ग को अपने अधिकार में लेने के लिए 7 सितम्बर, 1960 को एक मसौदा योजना प्रकाशित की गई थी। अपीलकर्ता ने अधिसूचना द्वारा अनुमत समय के भीतर मसौदा योजना पर आपत्तियां कीं। राज्य सरकार ने नियमों के नियम 7 के तहत आपत्तियों को सुनने और निर्णय लेने के लिए लीगल रिमेंबरेंसर की नियुक्ति की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच कला के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन किया गया था। अधिनियम की धारा 68– डी कि संवैधानिकता और राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों की वैधानिकता को कुछ बस संचालकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। । इस आवेदन को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ–साथ* नियम 7(6) पर विचार करते हुए निर्णय लिया। आपत्तियों की सुनवाई करने वाले अधिकारी के लिए मसौदा योजना को रद्द करना खुला नहीं था और ऐसा लगता है कि धारा 68–डी (2) अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। यह निर्णय 9 नवंबर, 1960 को दिया गया था। मसौदा योजना 21 नवंबर, 1960 को आपत्तियों को सुनने के लिए नियुक्त अधिकारी के समक्ष विचार के लिए आई थी। उनके समक्ष एक आवेदन किया गया था कि अपीलकर्ता को तथ्य के बिंदुओं पर साक्ष्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए जो आवेदन में इसलिए सुनाए गए ताकि अधिकारी आपत्तियों पर न्यायोचित निर्णय लेने की स्थिति में हो सकें। इस आवेदन को अधिकारी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। यह मामला 23 नवंबर, 1960 को विचार के लिए आया। उस तारीख को एक और आवेदन किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अपीलकर्ता यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना चाहता था कि मसौदा योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए, और यह तर्क दिया गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का दृष्टिकोण कि किसी अधिकारी के पास किसी मसौदा योजना को रद्द करने का अधिकार नहीं है, गलत था। इस आवेदन को भी अधिकारी ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले से हाथ–पैर बंधे हुए

है और यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या में कुछ भी गलत था तो समाधान कहीं और होगा। इसके बाद अधिकारी ने अपीलकर्ता की सुनवाई इस अर्थ में की कि उसने अपीलकर्ता की ओर से दलीलें सुनीं और 7 दिसंबर, 1960 के अपने आदेश द्वारा मसौदा योजना को मंजूरी दे दी अनुमोदित योजना तब 12 दिसंबर, 1960 को प्रकाशित की गई थी। 9 जनवरी, 1961 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उसका परमिट 26 जनवरी, 1961 या उसके बाद की तारीख से रद्द कर दिया गया था, जब से राजस्थान राज्य रोडवेज की बसें उपर्युक्त मार्ग पर संचालित होनी शुरू हुई। इस बीच, अपीलकर्ता ने असफल रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया और इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति की उसकी प्रार्थना भी खारिज कर दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया जिसे मंजूर कर लिया गया; और इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है।

अपीलकर्ता की ओर से हमारे समक्ष दो मुख्य बिंदुओं पर आग्रह किया गया है, अर्थात्, (i) अधिकारी का यह दृष्टिकोण गलत था कि ड्राफ्ट योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करना उसके लिए खुला नहीं था, और (ii) अधिकारी यह मानना गलत था कि वह साक्ष्य नहीं ले सकता, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, और वह सब जो उसे अधिनियम के धारा 68–डी के तहत करना था। वह दोनों पक्षों की दलीलें सुनना था। यह तर्क दिया गया है कि अधिकारी के इन दो गलत निर्णयों के मद्देनजर धारा के तहत आपत्तियों से निपटने के लिए उसे क्या करना है, इसका दृष्टिकोण धारा 68–डी के तहत काफी गलत था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तियों की कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई और इन परिस्थितियों में योजना को दी गई कोई भी मंजूरी अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलकर्ता वास्तविक अर्थों में "सुने जाने का हकदार है। जिसमें उन शब्दों का प्रयोग धारा 68–डी (2) में है।

दोबारा । (i)।

धारा 68–डी (2) जिससे हमारा संबंध है वह इन शब्दों में है:–

> "राज्य सरकार, आपत्तियों पर विचार करने के बाद और आपत्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों और राज्य परिवहन उपक्रम के प्रतिनिधियों को मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि वे चाहें, तो योजना को मंजूरी दे सकती है या संशोधित कर सकती है।"

9 नवंबर, 1960, के अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई राय यह है कि यह धारा इस योजना को रद्द करने की बात को उचित नहीं ठहराती है। हमारी राय है कि यह

दृष्टिकोण सही नहीं है. क्या धारा 68–डी (2) में प्रावधान है कि पक्षों को सुनने के बाद, राज्य सरकार मसौदा योजना को मंजूरी या संशोधित कर सकती है। हमारी राय में इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस प्राधिकारी को योजना को मंजूरी देनी है या संशोधित करना है, उसके पास यह भी शक्ति है, यदि वह उचित समझे, तो योजना को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे सकता है। राज्य सरकार के समक्ष पहले धारा 68–डी (2), क्या एक मसौदा योजना है। वह उपधारा यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार योजना को मंजूरी दे सकती है या संशोधित कर सकती है; इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार संशोधन के साथ या बिना संशोधन के योजना को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। जिस प्राधिकारी को किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने या संशोधित करने की शक्ति दी गई है, हमारी राय में उसके पास निश्चित रूप से यह कहने की शक्ति है कि वह प्रस्ताव को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देगा, उचित व्याख्या पर "अनुमोदन दे सकता है" शब्दों में "अनुमोदन नहीं कर सकता" भी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति अनुमोदन कर सकता है तो वह अनुमोदन करने के लिए बाध्य नहीं है। उस चरण तक जब उप–धाराओं (2) के तहत सुनवाई होती है, मसौदा योजना केवल राज्य सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव है और यह केवल तभी प्रभावी होगी जब वह इसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के मंजूरी दे देगी। लेकिन इस शक्ति का तात्पर्य यह कहने की शक्ति से स्पष्ट है कि वह योजना के मसौदे को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देती है; और यदि यह ऐसा कहता है, तो मसौदा योजना खारिज कर दी जाएगी और राज्य परिवहन उपक्रम को अनुमोदन के लिए एक और योजना प्रस्तुत करनी पड़ सकती है। जब धारा 68–ई रद्द करने की बात करता है, यह धारा68–डी (3), के तहत पहले से ही स्वीकृत योजना को संदर्भित करता है। और उस अध्याय में "रद्दीकरण" शब्द का उचित प्रयोग किया गया है। लेकिन तथ्य यह है कि धारा 68–ई एक योजना को रद्द करने का प्रावधान करता है जिसे पहले ही मंजूरी दे दी गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह धारा 68–डी(2) के तहत राज्य सरकार के लिए खुला नहीं है यह कहना कि, आपत्तियों को सुनने के बाद वह उस योजना को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देता है जो मंजूरी के लिए ड्राफ्ट के रूप में उसके सामने रखी गई थी। इसलिए हमारी राय है कि धारा 68–डी (2) के तहत आपत्तियों को सुनने के बाद राज्य सरकार यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि यह मसौदा योजना को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देती है, ऐसी स्थिति में मसौदा योजना खारिज कर दी जाएगी और राज्य परिवहन उपक्रम को नए सिरे से अध्याय IV–A में दी गई प्रक्रिया के अनुसार योजना बनानी पड़ सकती

है। इसलिए अधिकारी गलत था। यह मानते हुए कि उनके पास इस योजना को अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं थी कि वह इसकी मंजूरी को पूरी तरह से रोक सकते थे, हालांकि हम यह जोड़ सकते हैं कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे।

जहां तक नियमों के नियम 7(6) का सवाल है में यह धारा 68– डी(2) के समान है और इसलिए इसका मतलब वही होना चाहिए जो हमने धारा 68–डी(2) के संबंध में ऊपर कहा है। यदि, तथापि, नियम 7(6) में "करेगा" शब्द के उपयोग के स्थान पर शब्द "हो सकता है" जो धारा 68 डी(2) में आता है का इरादा आपत्तियों को सुनने वाले अधिकारी की शक्ति को कम करना है, यह नियम खराब होगा क्योंकि धारा 68 डी (2) में जो प्रावधान किया गया है उससे आगे जाना होगा। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि नियम 7(6) में "करेगा" शब्द का उपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां अंग्रेजी व्याकरण के नियमों के अनुसार "करेगा" शब्द का उपयोग किया जाना था और धारा 68–डी (2) में प्रयुक्त "हो सकता है" शब्द से अधिक कोई ताकत नहीं है।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर – राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित हुए जनरल ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि जो हमने ऊपर कहा है वह धारा 68–डी(2) और नियम 7(6) में सही स्थिति है।

पुनः (ii)

अगला प्रश्न यह है कि धारा 68–डी (2) के तहत सुनवाई का दायरा है। अधिकारी ने माना है कि सुनवाई का दायरा केवल तक की सुनवाई तक ही सीमित है और इससे अधिक नहीं, और यही कारण है कि उन्होंने प्रमुख साक्ष्य के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया, चाहे मौखिक या दस्तावेजी। अब *गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1)* में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि धारा 68–डी के तहत सुनवाई करते समय एक राज्य सरकार एक अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करती है। सुनवाई का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार को धारा 68–सी के तहत गठित राज्य परिवहन उपक्रम की राय से संतुष्ट होना है, अर्थात् यह योजना एक कुशल, पर्याप्त, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से है, सही है। सभी आपत्तियाँ यह दिखाने के लिए की गई हैं कि यह योजना एक कुशल, पर्याप्त, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान नहीं करती है।

(1) [1959] अनुपूरक 1 एससीआर 319

इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मसौदा योजना इस प्रकृति की परिवहन सेवा प्रदान करती है, एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार को उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामग्री की आवश्यकता हो सकती है। एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई नहीं होती है केवल एक तर्क का मतलब है; उचित मामलों में इसमें मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य लेना शामिल हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि धारा 68– डी(2) में निहित प्रावधान की परिस्थितियों में। और उसके तहत सुनवाई का उद्देश्य, साक्ष्य लेना, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, जो किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछित हो, राज्य सरकार के संबंध में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आवश्यक हो सकता है। योजना के प्रारूप पर आपत्तियां इसलिए हम उस अधिकारी से सहमत नहीं हो सकते कि धारा 68– डी(2) के तहत सुनवाई में कोई भी साक्ष्य लेने का कोई वारंट नहीं है। हमें ऐसा लगता है, आपत्तियों की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए सुनवाई दी गई है, उस पर विचार करते हुए, साक्ष्य का उत्पादन, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी धारा 68–डी (2) में विचार की गई सुनवाई के भीतर समझा जाता है। इसलिए अधिकारी यह अभिनिर्धारित करने में गलत था कि पार्टियों के लिए उसके सामने सबूत पेश करना खुला नहीं था और वे केवल एक ओर मसौदा योजना के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करने और दूसरी ओर अपनी लिखित आपत्तियों तक ही सीमित थे।

हालाँकि, हम यह बता सकते हैं कि साक्ष्य (वृत्तचित्र या मौखिक) प्रस्तुत करने का मतलब यह नहीं है कि पक्ष अपनी इच्छानुसार किसी भी मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्यवाही को असामान्य रूप से बढ़ा सकते हैं और सुनवाई करते समय राज्य सरकार इसे जाँचने में शक्तिहीन होगी। हमें केवल यह इंगित करने की आवश्यकता है कि यद्यपि साक्ष्य को धारा 68–डी (2) के अंतर्गत लेना पड़ सकता है। का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में साक्ष्य आवश्यक होगा। इसलिए यह राज्य सरकार या इस मामले में संबंधित अधिकारी पर निर्भर करेगा कि यदि कोई पक्ष साक्ष्य देना चाहता है तो यह निर्णय ले कि क्या साक्ष्य उसके समक्ष जांच के लिए आवश्यक और प्रासंगिक है। यदि यह मानता है कि साक्ष्य आवश्यक है, तो यह साक्ष्य प्रस्तुत करने के इच्छुक पक्ष को जांच के लिए प्रासंगिक और कारण के भीतर साक्ष्य देने का उचित अवसर देगा और इसके पास साक्ष्य देने और

रिकॉर्ड करने को नियंत्रित करने की सभी शक्तियाँ होंगी जो कोई भी न्यायालय है। इसलिए राज्य सरकार या सुनवाई करने वाले अधिकारी की इस सर्वव्यापी शक्ति के अधीन, पक्ष धारा 68–डी(2) के तहत सुनवाई के दौरान दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य देने के हकदार हैं।

हमने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर इस मामले में अधिकारी का दृष्टिकोण दोनों बिंदुओं पर गलत था। उनका यह विचार गलत था कि योजना को पूरी तरह से अस्वीकार करना और अनुमोदन को पूरी तरह से रोकना उनके लिए खुला नहीं था। उनका यह विचार भी गलत था कि साक्ष्य लेना उनके लिए खुला नहीं था, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, हालाँकि, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, इस साक्ष्य पर नियंत्रण उनका होना चाहिए। हमारे मन के प्रति इस गलत दृष्टिकोण का परिणाम निश्चित रूप से यह हुआ है कि अपीलकर्ता को वह सुनवाई नहीं मिली जिसका वह धारा 68 डी (2) के तहत हकदार था। इन परिस्थितियों में हमें यह मानना चाहिए कि योजना की मंजूरी धारा 68–डी (2) के तहत उचित सुनवाई के बिना थी।, जो, भले ही इस मामले में पूरी दलीलें सुनी गई हों, संबंधित अधिकारी द्वारा योजना को दी गई मंजूरी को रद्द कर देता है इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और योजना को मंजूरी देने वाले संबंधित अधिकारी के आदेश को रद्द कर देते हैं और निर्देश देते हैं कि मसौदा योजना पर उक्त अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जाए जिसे राज्य सरकार इसके बाद हमारे द्वारा ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में सुनवाई के बाद नियुक्त कर सकती है। अपीलकर्ता को उसका हर्जा राजस्थान राज्य से प्राप्त होगा।

इन परिस्थितियों में रिट याचिका में कोई आदेश आवश्यक नहीं है, जिसे खारिज किया जाता है। हम रिट याचिका में हर्जा के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

*याचिका खारिज।*

Vetted by:–
Smt. Monika
Add. Civil judge (J.D) IV
Amroha (U.P.)